अस्वीकरण

यह पूर्ण दस्तावेज़ का सारांश संस्करण है। पूर्ण दस्तावेज http://seci.co.in/web-data/docs/Revised%20draft%20RAP-160%20MW%20hybrid%20projecyt%20at%20Ramagiri.pdf पर प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी विसंगति / अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) - हाइब्रिड परियोजना

कार्यकारी सारांश

1.1 परिचय

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका इरादा पवन-सौर हाइब्रिड परियोजना का विकास करना है। इस परियोजना में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी और मुथुवाकुंतला गांव में ऊर्जा भंडारण सुविधा सहित कुल 160 मेगावॉट ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता होगी ।

सौर-पवन हाइब्रिड पार्क के लिए 'सौर ऊर्जा और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी (आईएसपीएचटी) परियोजना में नवीकरण' के इसके एक भाग के रूप में विश्व बैंक से विशेष ऋण की सहायता दी गई है। परियोजना का स्वामित्व सेकी के पास रहेगा और परियोजना के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा सेकी द्वारा आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की पूर्व सहमति से दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार के माध्यम से आंध्र प्रदेश डिस्काम को बेची जाएगी।

1.2 परियोजना विवरण

प्रस्तावित सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत परियोजना में 120 मेगावॉट क्षमता वाले सौर पीवी फार्म, 40 मेगावॉट क्षमता का पवन फार्म की स्थापना, बैटरी भंडारण सुविधा और रामगिरी पूलिंग स्टेशन से हिंदुपुर ग्रिड तक लगभग 45 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। प्रस्तावित सौर-पवन हाइब्रिड पार्क आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के रामगिरी गांव (मंडल - रामगिरी) और मुथुवाकुंतला (मंडल- कनगनापल्ली) में पड़ता है। पहचान किए गए स्थल की भौगोलिक स्थिति 14°21' 29.7" उत्तरी अक्षांश और 77°31' 18.9" पूर्वी रेखांश है।

1.3 कार्यप्रणाली

कार्य योजना प्राथमिक और माध्यमिक डेटा स्रोतों की समीक्षा पर आधारित है। व्यापक आधारभूत स्थिति और स्थानीय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) / परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की कानूनी हकदारी की पहचान करने के लिए गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किए गए थे। वास्तविक स्थिति का पता लगाने / सत्यापित करने, परियोजना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, भौतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक प्रकृति का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से माध्यमिक डेटा / जानकारी एकत्र की गई थी।

1.4 भूमि की आवश्यकता

प्रस्तावित हाइब्रिड पार्क के लिए कुल 889.93 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। लगभग (72%) प्रभावित भूमि निर्दिष्ट भूमि है और शेष (28%) सरकारी भूमि है। निर्दिष्ट भूमि 216

परिवारों की है जो परियोजना प्रभावित परिवार हैं। शेष सरकारी भूमि का हस्तांतरण मौजूदा सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

1.5 परियोजना क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 73,674 है जिसमें 51.43% पुरुष हैं और 48.57% महिलाएं हैं। अध्ययन क्षेत्र का औसत लिंग अनुपात लगभग प्रति 1000 पुरुष 944 महिलाएं हैं, जो प्रति 1000 पुरुषों 933 महिलाओं की राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी बेहतर है। कुल अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अध्ययन क्षेत्र की पूरी जनसंख्या को 17,544 घरों में बांटा गया है और औसत घरेलू आकार लगभग 4.12 व्यक्ति / घर है। अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 18.81% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जाति 15.10% है और 3.71% अनुसूची जनजाति समुदाय से संबंधित है।

अध्ययन क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 53.21% (18.091) है जिसमें पुरुष साक्षरता 61.85% है और महिलाओं की साक्षरता 44.18% है जिसमें लिंग अंतर 17.67% बैठता है। काम करने वाले व्यक्तियों के औद्योगिक वर्गीकरण पर जनगणना डेटा दर्शाता है कि 38.03% किसान हैं, 45.70% हैं कृषि मजदूर, 1.71% घरेलू उद्योग में नियोजित हैं और 14.57% अन्य कामगारों की श्रेणी में आते हैं।

1.6 प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करना

विश्व बैंक परिचालन नीति 4.12 के अनुसार अनौपचारिक पुनर्वास पर, कृषि भूमि और आजीविका के नुकसान के संबंध में तत्काल परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने और कम करने के लिए डिजाइन स्तर पर प्रयास किए गए थे। जहां यह व्यवहार्य नहीं था, सामाजिक मूल्यांकन ने इन प्रभावों को कम करने के लिए संभावित प्रतिकूल प्रभाव और न्यूनीकरण उपायों की पहचान की है। परियोजना निर्माण और प्रचालन के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना लाभ देना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना में इन आकलनों और न्यूनीकरण उपायों को ध्यान में रखा जाएगा।

1.7 लिंग नीति और महिलाओं की भागीदारी

जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग पीएपी की 48% महिलाएं हैं। इस समूह में 21 महिलाएं भी परिवारों (डब्ल्यूएचएच) की मुखिया हैं, और कमजोर सामाजिक समूहों / परिवारों (अ.जा. / अ.ज.जा.) से महिलाएं हैं जो सौर हाइब्रिड पार्क परियोजना से प्रभावित होंगी। लिंग नीति और महिलाओं की भागीदारी भाग में स्त्री पुरुष के अंतर और ईएसआईए के दौरान पहचान किए गए मुद्दों की रूपरेखा तैयार की जाती है और महिलाओं और पुरुषों के लिए परियोजना के न्यायसंगत परिणामों और लाभों के लिए इन्हें हल करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करता है।

1.8 सामुदायिक भागीदारी और परामर्श

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के एक अभिन्न अंग के रूप में जनता से परामर्श किए गए थे। इन परामर्शों के दौरान, हितधारकों को प्रस्तावित परियोजना के बारे में सूचित किया गया था और उनके विचार और सुझाव दर्ज किए गए थे। इस प्रक्रिया ने समुदाय के विभिन्न समूहों के प्रमुख मुद्दों, आवश्यकताओं और चिंताओं की पहचान करने में मदद की थी।

1.9 लागू नीतियां और आर एंड आर ढांचा

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, भारत सरकार और सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी विश्व बैंक नीतियों में परियोजना कार्रवाई के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने और न्यूनीकरण करने और सकारात्मक प्रभाव, स्थायित्व और विकास लाभों को बढ़ाने के लिए डिजाइन स्थिति के दौरान किए जाने वाले सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित परियोजना के लिए ईएसएमएफ विकसित किया गया है जिसमें आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, अन्य राष्ट्रीय और राज्य सरकार के कानून; और अनौपचारिक पुनर्वास पर विश्व बैंक की प्रचालन नीतियां ओपी 4.12 के आधार पर परियोजना के सभी घटकों के लिए आरपीएफ शामिल हैं। आरपीएफ के भाग के रूप में, एक आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और विश्व बैंक के ओपी 4.12 के प्रावधानों के आधार पर एक हकदारी मैट्रिक्स विकसित किया गया है। प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए न्यूनीकरण उपायों को भी आरएपी में शामिल किया गया है।

1.10 परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी)

हाइब्रिड पार्क के कारण कुल 216 परिवार प्रभावित होंगे। इनमें से रामगिरी गांव के 135 प्रभावित परिवारों और मुथुवाकुंतला गांव के 60 प्रभावित परिवारों के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान शेष 21 प्रभावित परिवार अनुपस्थित थे (रामागिरी गांव में 7 परिवार और मुथुवुकुंतला में 14 प्रभावित परिवार)। पीएएफ और पीएपी का वितरण **तालिका 1.1** में दिया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों के परिवार का औसत आकार 3.99 है, जो 4.16 के जिला औसत से कम है।

तालिका 1.1 : परियोजना प्रभावित परिवार और व्यक्ति

प्रभावित गांव	**प्रभावित परिवारों की संख्या**	**प्रभावित व्यक्तियों की संख्या**
रामागिरी	142	559
मुथुवाकुंतला	74	303
जोड़	**216**	**862**

1.11 संस्थागत व्यवस्था और कार्यान्वयन योजना

पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) में योजना के कार्यान्वयन के लिए उचित संस्थागत प्रबन्ध और तंत्र के विवरण दिए गए हैं। सेकी के निगमित कार्यालय में एक पर्यावरण और सामाजिक/ जेंडर ऑफिसर होगा जिसकी सहायता के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना डेवलपर्स का एक प्रतिनिधि होगा। सेकी का क्षेत्रीय अधिकारी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली किसी भी तरह की शिकायतों के लिए संपर्क का पहला स्तर होगा। यह परिकल्पना की गई है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की गतिविधियां परियोजना शुरू होने के 15 महीने के अन्दर पूरी की जाएंगी।

1.12 शिकायत निवारण तंत्र

विवादों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य और परियोजना स्तर तथा सेकी में पर्याप्त जनशक्ति सहित एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जाएगी। शिकायतें, यदि कोई हों, तो व्यक्तिगत रूप से, संबंधित पते पर लिखित रूप में / ई-मेल या सेकी को सीधी कॉल के जरिए प्रस्तुत की जा सकती हैं।

1.13 कार्यान्वयन अनुसूची

सिविल कार्य कार्यान्वयन अनुसूची से स्पष्ट रूप से सम्बद्ध पुनर्वास कार्यान्वयन अनुसूची सहित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की एक विस्तृत कार्यान्वयन अनुसूची को आरएपी में शामिल किया गया है। भूमि और संबंधित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किया जाएगा, और जहां लागू हो, पुनर्वास स्थल और विस्थापन भत्ते की पीएपी में व्यवस्था की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी अनुमोदित अनुसूची के अनुसार आरएपी के सुचारु कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति / तैनाती सुनिश्चित करेगी।

1.14 प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आय बहाली

आरएपी के मुख्य उद्देश्यों का एक उद्देश्य पूर्व परियोजना स्तर स्थिति के लिए पीएपी की आजीविका स्थितियों को बहाल करना है। इस परियोजना के तहत आजीविका की बहाली और वृद्धि का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएपी कम से कम 'उनके पूर्व जीवन यापन स्तर को वापस पाने' में सक्षम हो। इस उद्देश्य के लिए कुछ प्रशिक्षण और आय सृजन अवसरों की पहचान की गई है।

1.15 निगरानी और मूल्यांकन

आरएपी निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) के लिए प्रावधान स्थापित करता है। सेकी आरएपी कार्यान्वयन की आंतरिक निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। एक बाहरी एजेन्सी को आरएपी कार्यान्वयन के मूल्यांकन और अनुपालन के लिए नियुक्त किया जाएगा।

1.16 लागत और बजट

बजट स्वरूप में संकेतक है और इसमें विभिन्न व्यय श्रेणियों के लिए परिव्यय शामिल है जिनकी गणना मौजूदा मूल्यों पर की गई है। लागत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना / राजस्व विभाग डेटा और वर्तमान बाजार मूल्यों के माध्यम से एकत्र की गई सूचना पर आधारित है। भूमि अधिग्रहण से कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक के लिए आरएण्डआर गतिविधियों के लिए सुझाया गया कुल बजटीय प्रावधान लगभग 23 करोड़ रुपये है। आरएपी कार्यान्वयन के लिए अनुमानित बजट नीचे सारणी 1.2 में दिया गया है।

सारणी 1.2

सेकी के अधीन ईएसएमएफ के प्रावधानों की हकदारी के अनुसार पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) के लिए अनुमानित लागत

क्र.सं.	मदें	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रुपयों में)	राशि (रुपयों में)
1	निर्दिष्ट भूमि	एकड़	643.85	3,25,000 *	20,92,51,250
2	कमजोर परिवारों के लिए सहायता (ईएम के अनुसार)	संख्या	216	50 , 000	1,08,00,000
3	पीएपी को प्रशिक्षण सहायता (ईएम के अनुसार)	परिवारों की संख्या	216	10 , 000	21,60,000
4	आरएपी और जीएपी कार्यान्वयन के एम एंड ई के लिए एजेंसी रखना	-	-	एकमुश्त	15,00,000

क्र.सं.	मदें	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रुपयों में)	राशि (रुपयों में)
5	जीआरसी	-	-	एकमुश्त	2,00,000
6	जनता में जागरूकता पैदा करना और निरंतर परामर्श करना			एकमुश्त	2,00,000
7	आजीविका और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण			एकमुश्त	22,50,000
8	बाहरी निगरानी और मूल्यांकन			एकमुश्त	10,00,000
9	आरएपी कार्यान्वयन एजेंसी			एकमुश्त	15,00,000
	उप-जोड़				**22,88,61,250**
10	आकस्मिकता कुल लागत का 2% की दर से				45,77,225
	कुल जोड़				**23,34,38, 475**

** सरकारी दर पर आधारित*